हिन्दी दैनिक

राष्ट्रीय स्वाभिमान

RNI No. : MAHHIN/2008/24084. www.rashtriyaswabhimaan.com

● वर्ष : 17 ● अंक : 61 ● मुंबई, शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 ● पृष्ठ : 4 ● मूल्य 1 रुपए

खबर संक्षेप

सबरीमाला सोना चोरी केस में बड़ा खुलासा, मुख्य आरोपी उन्निकृष्णन पोट्टी गिरफ्तार, 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया

तिरुवनंतपुरम। सबरीमाला मंदिर में हुई बहुचर्चित सोना चोरी मामले में केरल पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस केस के मुख्य आरोपी उन्निकृष्णन पोट्टी को गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 30 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि SIT ने गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात करीब ढाई बजे पोट्टी को हिरासत में लिया था। लगभग 14 घंटे तक चली गहन पूछताछ के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया।

कोर्ट ले जाते समय पोट्टी ने पत्रकारों से कहा कि उसे राजनीतिक और व्यक्तिगत षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है और असली दोषी जल्द ही सामने आएंगे। इस दौरान कोर्ट परिसर के बाहर माहौल तनावपूर्ण हो गया जब भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने आरोपी पर जूता फेंक दिया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को पकड़ लिया और भीड़ को नियंत्रित किया। मामला तब सामने आया जब केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मंदिर की द्वारपालक मूर्तियों पर चढ़ाए जाने वाले सोने के प्लेट्स के वजन में बड़ा अंतर पाया। जांच रिपोर्ट के अनुसार, जब ये प्लेट्स आरोपी उन्निकृष्णन पोट्टी को सौंपे गए थे, तब उनका कुल वजन 42.8 किलोग्राम था। लेकिन चेन्नई की "स्मार्ट क्रिएशंस" नामक कंपनी तक पहुंचते-पहुंचते यह वजन घटकर मात्र 38.2 किलोग्राम रह गया। इस अंतर ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। हाईकोर्ट ने ट्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड (TDB) की विजिलेंस विंग से प्रारंभिक जांच कराई। जांच में पाया गया कि सोने की परतों में गड़बड़ी केवल परिवहन या प्रोसेसिंग के दौरान ही हो सकती थी और इसमें पोट्टी की भूमिका संदिग्ध रही। इसके बाद अदालत ने इस मामले की व्यापक जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन करने का निर्देश दिया था। इस घटना ने न केवल सबरीमाला मंदिर प्रशासन बल्कि पूरे केरल के धार्मिक और राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। बताया जा रहा है कि यह मामला सिर्फ सोने की चोरी का नहीं, बल्कि मंदिर प्रशासन और ठेकेदारों के बीच संभावित भ्रष्टाचार की कड़ी का भी खुलासा कर सकता है। SIT को अब पोट्टी से पूछताछ के दौरान यह पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई है कि आखिर 4.6 किलो सोना कहां गया और इसमें किन अन्य लोगों की भूमिका रही। इस बीच ट्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड ने सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सबरीमाला मंदिर में नई तकनीक से निगरानी प्रणाली लगाने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को मंदिर के गर्भगृह के बाहर द्वारपालक मूर्तियों पर असली सोने की परत चढ़ाने का कार्य फिर से शुरू किया गया, जिसे बोर्ड के अधिकारियों की सीधी देखरेख में पूरा किया गया।

आंध्र-कर्नाटक के आईटी मंत्रियों में सोशल मीडिया पर गर्म जंग, निवेश को लेकर छिड़ी जुबानी बहस

अमरावती। दक्षिण भारत के दो तकनीकी केंद्र माने जाने वाले राज्यों — आंध्र प्रदेश और कर्नाटक — के बीच आईटी क्षेत्र में निवेश को लेकर एक बार फिर जुबानी जंग छिड़ गई है। दोनों राज्यों के आईटी मंत्रियों ने एक-दूसरे पर सोशल मीडिया के माध्यम से तीखे तंज कसे हैं, जिससे यह बहस राजनीतिक रंग भी ले चुकी है। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश, जो पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के पुत्र हैं, ने हाल ही में एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, "कहते हैं आंध्र का खाना मसालेदार होता है, लगता है हमारे निवेश भी वैसे ही हैं। कुछ पड़ोसी पहले से ही इसकी गर्मी महसूस कर रहे हैं।" लोकेश ने दावा किया कि भारत के सबसे युवा राज्य को अब तक के सबसे बड़े विदेशी निवेश मिल रहे हैं। उन्होंने हाल में नई दिल्ली में हुए समझौते का हवाला देते हुए बताया कि गूगल आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में करीब 15 अरब डॉलर के एआई डाटा सेंटर की स्थापना करने जा रहा है। इस ट्वीट ने तुरंत राजनीतिक माहौल गरमा दिया। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे, जो पहले भी उद्योग निवेश पर आंध्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं, ने जवाबी ट्वीट में लिखा, "निवेश की घोषणा करना आसान है, लेकिन उसे धरातल पर उतारना मुश्किल। हमें कागज़ी समझौतों की नहीं, स्थायी रोजगार की ज़रूरत है। बेंगलुरु अब भी भारत की टेक राजधानी है, और आंकड़े यह खुद साबित करते हैं।"

डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा—यह न्याय व्यवस्था पर हमला है

नई दिल्ली। देश में तेजी से फैल रहे ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों ने अब सुप्रीम कोर्ट को भी चिंता में डाल दिया है। अदालत ने इस गंभीर अपराध पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार, सीबीआई और हरियाणा पुलिस से विस्तृत जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यह कोई साधारण आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि भारत की संपूर्ण न्याय व्यवस्था पर सीधा हमला है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अदालतों के नाम, आदेश, मुहर और जजों के हस्ताक्षर की फर्जी नकल कर लोगों को ठगना न केवल गंभीर अपराध है, बल्कि न्याय पर आम जनता के भरोसे को भी गहरा आघात पहुंचाने वाला कार्य है।

मामले की शुरुआत हरियाणा के अंबाला जिले से हुई, जहां 73 वर्षीय बुजुर्ग दंपती को 3 से 16 सितंबर के बीच ठगों ने 1.05 करोड़ रुपये की चपत लगा दी। आरोपियों ने खुद को जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर उन्हें वीडियो कॉल के माध्यम से 'डिजिटल अरेस्ट' कर लिया। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय एजेंसियों के नकली आदेशों और जजों के फर्जी सिग्नेचर दिखाए। जब महिला पीड़िता ने 21 सितंबर को चीफ जस्टिस बी. आर. गवई को पत्र लिखकर अपनी व्यथा बताई, तब सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया और केंद्र सरकार को जवाब देने का आदेश जारी किया।

अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों की संख्या देशभर में लगातार बढ़ रही है और इनका जाल केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है। इसलिए केंद्र और राज्य की पुलिस एजेंसियों को मिलकर एक संयुक्त राष्ट्रीय अभियान चलाना चाहिए, ताकि इस संगठित साइबर अपराध नेटवर्क को समाप्त किया जा सके। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस विषय पर विस्तृत सहायता मांगी है और हरियाणा सरकार व अंबाला साइबर क्राइम यूनिट को अब तक की जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

इसी बीच मुंबई पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए "डिजिटल अरेस्ट" के नाम पर साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गुजरात के मेहसाणा और अहमदाबाद से छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने देशभर में कई लोगों को निशाना बनाया, जिनमें एक 72 वर्षीय व्यापारी से 58 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सबसे चर्चित है। पुलिस जांच में सामने आया कि यह गिरोह अंतरराष्ट्रीय ठगों से सीधा जुड़ा हुआ था, जिनके ठिकाने चीन और कंबोडिया में हैं। गिरोह का सरगना युवराज उर्फ मार्को उर्फ लक्ष्मण सिंह सिकरवार बताया गया है, जो पिछले तीन वर्षों से साइबर अपराध में सक्रिय था। आरोपियों की गिरफ्तारी से खुलासा हुआ कि वे खुद को सीबीआई, ईडी, एनआईए या एटीएस का अधिकारी बताकर लोगों को धमकाते थे। फिर उन्हें वीडियो कॉल पर "डिजिटल अरेस्ट" में रखकर मानसिक दबाव बनाते थे और बैंक खातों से करोड़ों की ठगी कर लेते थे। ठगी की रकम को कई बैंक खातों में घुमाकर अंततः क्रिप्टोकरेंसी और अमेरिकी डॉलर में बदल दिया जाता था।

अब तक पुलिस ने 15 बैंक खाते सीज किए हैं और करीब 10.5 लाख रुपये रोक लिए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि इस गिरोह के खिलाफ 13 राज्यों में 31 से अधिक साइबर फ्रॉड के मामले दर्ज हैं, जिनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, तेलंगाना, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जा रही यह साइबर ठगी न केवल आर्थिक अपराध है बल्कि यह देश की न्याय व्यवस्था, कानून की प्रतिष्ठा और जनता के विश्वास पर भी घातक प्रहार है। अदालत ने संकेत दिए कि यदि केंद्र और राज्य एजेंसियों ने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए तो न्यायपालिका स्वयं सख्त दिशा-निर्देश जारी कर सकती है, ताकि किसी निर्दोष नागरिक को फिर से "फर्जी अदालत" के नाम पर बंधक न बनाया जा सके।

लेह हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी.एस. चौहान होंगे जिम्मेदार, सरकार ने की औपचारिक घोषणा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज बी.एस. चौहान को नियुक्त करने की घोषणा की है। इस हिंसा ने प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए थे, और अब सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से हो।

गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस न्यायिक जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि 24 सितंबर को लेह शहर में गंभीर कानून और व्यवस्था की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, पुलिस ने किस तरह कार्रवाई की, और उस दौरान चार व्यक्तियों की मौत कैसे हुई। मंत्रालय ने कहा कि जांच के तहत सभी पहलुओं — सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया, प्रदर्शनकारियों की गतिविधियां, और प्रशासनिक फैसलों — की बारीकी से पड़ताल की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, 24 सितंबर को लेह में सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि लेह को राज्य का दर्जा दिया जाए और छठे अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया जाए। इस दौरान हिंसा भड़क गई और चार लोगों की मौत के साथ लगभग 90 लोग घायल हो गए। घटनाओं के दो दिन बाद, पुलिस ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत गिरफ्तार किया और उन्हें जोधपुर जेल भेजा गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने हिंसा भड़काने में भूमिका निभाई।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह किसी भी समय संवाद के लिए तैयार है। एपेक्स बॉडी लेह (ABL) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के साथ बातचीत को सरकार स्वागत योग्य मानती है और भरोसा जताया है कि लगातार बातचीत से जल्द ही सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। मंत्रालय ने कहा कि लेह के लोगों की आकांक्षाओं और हितों के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस न्यायिक जांच की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी.एस. चौहान को सौंपी जाने से जांच की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़ेगी। यह जांच न केवल उन घटनाओं की समीक्षा करेगी, बल्कि भविष्य में ऐसी हिंसा और कानून व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण सिफारिशें कर सकती है। लेह हिंसा की जांच का यह कदम उस क्षेत्र में सुरक्षा, लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर उठाया गया एक अहम प्रयास माना जा रहा है। आगामी रिपोर्ट से पता चलेगा कि प्रशासन ने किन कारणों से स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाया और आगे के लिए कौन-से सुधार आवश्यक हैं।

अगले दशक में वायु शक्ति का बड़ा निवेश: लड़ाकू विमानों के इंजन पर भारत खर्च करेगा लगभग 6.54 लाख करोड़ रुपए

नई दिल्ली। रक्षा उत्पादन और वायु शक्ति को मजबूत करने की दिशा में सरकार एक बड़े पैमाने का निवेश करने जा रही है — अगले दस वर्षों के भीतर भारत लड़ाकू विमानों के इंजन खरीद और निर्माण पर लगभग 6.54 लाख करोड़ रुपए (करीब 7.4 अरब डॉलर) खर्च करेगा। यह आंकड़ा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के निदेशक एस.वी. रमण मूर्ति ने शुक्रवार को साझा किया। उन्होंने बताया कि देश को 2035 तक कुल मिलाकर लगभग 1,100 इंजन जरूरत पड़ने की संभावना है, जो विभिन्न विमानों और उनके संस्करणों में इस्तेमाल होंगे। यह खर्च केवल आयातित इंजनों की खरीद तक सीमित नहीं रहेगा; घरेलू क्षमता बढ़ाने और स्वदेशी एविएशन इकोसिस्टम को सशक्त करने की योजना भी इसमें समाहित है। कावेरी इंजन परियोजना, जो पिछले कई वर्षों से तेजस के लिए स्थानीय शक्ति स्रोत विकसित करने के लक्ष्य से जुड़ी रही, तकनीकी चुनौतियों के कारण पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाई। फिर भी विशेषज्ञों और नीति-निर्माताओं की नजर अब कावेरी के संशोधित संस्करण पर है — ऐसे संस्करण जिन्हें मानव रहित लड़ाकू विमानों (UCAV) या कुछ अन्य प्लेटफॉर्म पर तैनात करने पर विचार किया जा रहा है। इससे स्वदेशी इंजनों के विकास को नई दिशा और उपयोगिता मिलेगी।

आगामी पीढ़ियों के लड़ाकू विमानों के लिए भारत ने पहले से ही ambicious कार्यक्रम शुरू कर रखे हैं। पाँचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट — जिसे एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) कहा जाता है — के लिए भी स्वदेशी या सह-विकसित इंजन की आवश्यकता होगी। रमण मूर्ति ने संकेत दिया कि इस स्टेल्थ विमान के लिए तीन बड़े विदेशी इंजन निर्माताओं — फ्रांस की सैफरान, ब्रिटेन की रॉल्स-रॉयस और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक — ने सह-विकास या साझेदारी में रुचि दिखाई है। यदि ये सह-भागीदारी स्थापित होती हैं, तो यह भारत में उन्नत गैस टरबाइन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, परीक्षण सुविधाओं और वैधानिक लाइसेंसिंग के माध्यम से स्थानीय विनिर्माण को गति दे सकती है।

वर्तमान योजना का एक लक्ष्य यह भी है कि निजी क्षेत्र को रक्षा परियोजनाओं में अधिक सक्रिय रूप से शामिल किया जाए। सरकार की मंशा है कि कुछ प्रमुख परियोजनाओं में निजी कंपनियों को भी बोली लगाने और उप-निर्माण (subcontracting) में अवसर मिलें — इससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) पर एकांगी निर्भरता कम होने और पूर्ति श्रृंखला (supply chain) में विविधता आने की उम्मीद है। साथ ही, वैश्विक विनिर्माण और तकनीकी साझेदारी के जरिये देश की डेवलपमेंट रफ्तार तेज होगी और विनिर्माण इकाइयों में रोज़गार भी बढ़ने की संभावना है।

गृह मंत्रालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जज नेल्सन सैलो की अध्यक्षता में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण का गठन किया

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार, 17 अक्तूबर को गृह मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नेल्सन सैलो के नेतृत्व में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण का गठन करने की घोषणा की है। इस न्यायाधिकरण का मुख्य उद्देश्य यह तय करना है कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [NSCN (K)] और उसके सभी गुट, शाखाएँ तथा अग्रिम संगठन वास्तव में गैरकानूनी संघ घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त कारण रखते हैं या नहीं।

अधिसूचना के अनुसार, यह न्यायाधिकरण 1967 के विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत गठित किया गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि न्यायाधिकरण का गठन विशेष रूप से यह जांचने के लिए किया गया है कि क्या NSCN (K) देश की संप्रभुता, अखंडता और कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करता है और क्या इसके सभी गुटों और शाखाओं को गैरकानूनी घोषित करना उचित होगा।

इससे पहले, 22 सितंबर 2025 को गृह मंत्रालय ने NSCN (K) और उसके सभी गुटों, शाखाओं एवं अग्रिम संगठनों को पांच साल की अवधि के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया था। मंत्रालय ने बताया था कि यह संगठन देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल रहा है। इसके तहत संगठन पर आपराधिक गतिविधियों, हथियार सौदों और राज्य विरोधी षड्यंत्रों में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायाधिकरण का गठन इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी निर्णय सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। न्यायाधिकरण की रिपोर्ट और सिफारिशें आने वाले महीनों में यह तय करेंगी कि NSCN (K) और उसके संबंधित संगठन देश में गैरकानूनी घोषित रहेंगे या नहीं, और किस हद तक सुरक्षा बलों और प्रशासनिक संस्थाओं को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस न्यायाधिकरण की प्रक्रिया के दौरान सभी पक्षों को अपनी दलील पेश करने का पूरा अवसर मिलेगा, ताकि निष्पक्ष और कानूनी दृष्टि से ठोस निर्णय लिया जा सके। यह कदम विशेष रूप से उत्तरी पूर्वी भारत में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है, और इससे वहां के निवासियों और प्रशासनिक तंत्र को भविष्य में किसी भी प्रकार के हिंसक या अवैध गतिविधियों से निपटने में मदद मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन जुआ–सट्टा मामले में केंद्र को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने की। कोर्ट ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकार के वकील को याचिका की कॉपी उपलब्ध कराने का आदेश दिया, ताकि वे अगली सुनवाई में कोर्ट को मदद कर सकें।

याचिका सेंटर फॉर एकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टेमिक चेंज (CASC) और शौर्य तिवारी ने दायर की थी। इसमें कहा गया है कि देशभर में तेजी से फैल रहे ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी एप्स को रोकना जरूरी है। वर्तमान में लगभग 65 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं, जिसमें ज्यादातर लोग रियल मनी गेम्स में दांव लगाते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स का सालाना कारोबार 1.8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का अनुमान है।

याचिकाकर्ताओं ने लॉ कमीशन की 276वीं रिपोर्ट और महाभारत का भी हवाला दिया। रिपोर्ट में उल्लेख है कि यदि महाभारत के समय जुआ नियंत्रित होता, तो युधिष्ठिर अपनी पत्नी और भाइयों को दांव पर नहीं लगाते। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतावनी है कि अनियंत्रित जुआ समाज की नींव हिला सकता है।

साथ ही याचिकाकर्ताओं ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के संसद में दिए गए बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन मनी गेम्स ड्रग्स से बड़ा खतरा बन चुके हैं, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिद्म ऐसे हैं कि हार लगभग निश्चित रहती है।

याचिका में किए गए प्रमुख दावे

1.केंद्र का नया कानून राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेपः
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सातवीं अनुसूची के अनुसार जुआ राज्यों का विषय है। केंद्र का नया कानून राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है और बेटिंग को विनियमित करने के बजाय वैधता देने का मार्ग खोलता है।

2.कर चोरी का मामलाः
डीजीजीआई ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से जुड़े 81,875 करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़ी है। इसमें 642 ऑफशोर कंपनियां शामिल हैं, जो देश में बिना टैक्स दिए जुआ चला रही हैं। अधिकांश विदेशी सर्वरों पर संचालित होने के कारण यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी है।

3.बच्चों और युवा पीढ़ी पर प्रभावः
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि फिल्मी सितारे और क्रिकेटर इन एप्स का प्रचार कर रहे हैं, जिससे बच्चों और किशोरों को गलत दिशा में प्रभावित किया जा रहा है। अभिनेता अक्षय कुमार के हवाले से बताया गया कि उनकी 13 साल की बेटी को ऑनलाइन गेम के दौरान यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

इसके अलावा, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि "ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर" अब एक मानसिक बीमारी के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर माना और केंद्र सरकार से कहा कि याचिका की कॉपी देखकर वे अगली सुनवाई में पूरी मदद करें, ताकि देशभर में ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। यह मामला विशेष रूप से बच्चों, युवा और राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील माना जा रहा है।

संपादकीय

जन-संवाद की सुबह, फाइल-मंथन की सांझ

पहली नजर में बड़े पद की चमक-दमक का अपना सम्मोहन होता है, लेकिन हकीकत में जिम्मेदारी-जवाबदेही व विपरीत चुनौतियों में सामंजस्य बैठाना कांटों का ताज पहनने जैसा ही होता है। अंतहीन जन-अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना उतना ही कठिन होता है। वैसे किसी सत्ता का एक साल बहुत लंबी अवधि नहीं होती। उसके आधार पर अंतिम मूल्यांकन करना भी जल्दबाजी ही कही जाएगी, लेकिन इससे किसी नेतृत्व या सरकार की दिशा-दशा को बोध तो हो जाता है। कमोबेश, यह कसौटी हरियाणा में एक साल पूरा कर रही नायब सैनी सरकार के लिये भी है। सामाजिक न्याय के समीकरण संतुलन की कवायद के क्रम में भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने वाले नायब सैनी की इस पद पर ताजपोशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पसंद रही है। जब नरेंद्र मोदी चंडीगढ़-हरियाणा में संगठन का दायित्व निभा रहे थे, तो सैनी उनके कार्यालय सहयोगी थे। इस मायने में बिना राजनीतिक व समृद्ध आर्थिक पृष्ठभूमि के राज्य के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने को एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। उनके राजनीतिक विरोधी भी उनकी सदाबहार मुस्कान-विनोदप्रियता के कायल रहे हैं। वे विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं को सम्मान सार्वजनिक रूप से देते नजर आते हैं, लेकिन पिछले विधानसभा सत्र में मुद्दों पर विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लेने से भी वे नहीं चूके। वैसे तो उनके एक साल के कार्यकाल में कई चुनौतियां सामने आती-जाती रही हैं, लेकिन हाल ही में एडीजीपी वाई.पूरन कुमार व एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या ने सरकार के सामने असहज स्थिति व बड़ी चुनौती पेश की। हालांकि, देर से ही सही फौरी तौर पर मामले का पटाक्षेप हुआ, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुद्दे की संवेदनशीलता को महसूस कर कदम बढ़ाए। एडीजीपी द्वारा आत्महत्या की खबर उन्हें जापान दौरे के दौरान मिली तो उन्होंने दौरे में शामिल उनकी पत्नी अमनीत को अधिकारियों के साथ तुरंत भारत भेजा। भारत आते ही खुद भी वे सीधे एडीजीपी के घर संवेदना व्यक्त करने पहुंचे, तो एएसआई संदीप लाठर के घर भी परिवार को संबल देने गए।

बहरहाल, ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ नायब सैनी को जरूर मिला है। कई विकास योजनाएं कायदे से सिरे चढ़ी हैं। लेकिन लाडो लक्ष्मी योजना ट्रंप कार्ड साबित हुई है। विधानसभा चुनावों में इस योजना के वायदे का छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र चुनावों की तर्ज पर हरियाणा में भी भाजपा को खासा लाभ मिला। मिले परिणामों ने तमाम कयासों को निरर्थक साबित किया। हर जरूरतमंद महिला को सरकार की तरफ से 21 सौ रुपये मिलना, उन्हें आर्थिक स्वावलंबन देना ही है। पहले चरण में बाइस लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। निस्संदेह, कमजोर वर्ग के लोगों के लिये अपनी छत का सपना पूरा करना एक दुष्कर कार्य है। हरियाणा सरकार ने दस हजार से अधिक आबादी वाले महाग्रामों में गरीबों को पचास-पचास गज व छोटे गांवों में सौ-सौ गज के प्लाट उपलब्ध कराये। शहरों में ये 25 गज के रहे। वहीं प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना के तहत मिलने वाले ढाई-ढाई लाख रुपये ने उनके घर के सपने को हकीकत बनाया। मुख्यमंत्री नायब सैनी की खासियत लोगों के साथ सहज उपलब्धता है। उनकी सुबह कबीर कुटीर में जन संवाद से शुरू होती है और रात फाइलों के साथ खत्म होती है। जनता के लिये सहज उपलब्धता और निरंतर संवाद लोकतंत्र की अपरिहार्य शर्त होती है। उनके चंडीगढ़ आवास में सुबह से ही मिलने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। निस्संदेह, आम जन ही सरकार को बेहतर फीडबैक दे सकते हैं, जो नौकरशाही की जटिलताओं के चलते सहज अभिव्यक्ति नहीं दे पाते। बेरोजगारी की समस्या किसी भी सरकार के लिये बड़ी चुनौती होती है। राज्य में चौबीस हजार बेरोजगारों को ग्रुप सी की नौकरियां देना राज्य सरकार की उपलब्धि के तौर पर देखा गया। वहीं लोकसेवा आयोग के माध्यम से 1311 पदों पर चयन और एचकेआरएन पोर्टल को पारदर्शी भर्ती प्रणाली के रूप में विकसित करना, राज्य सरकार की रोजगार के साथ स्थायित्व की नीति का संकेत माना जा सकता है। विश्वास किया जाना चाहिए कि नायब सरकार आने वाले चार सालों में जनाकांक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह खरी उतर पाएगी।

यूपी की राज्यपाल महिलाओं—बच्चों की बदहाली पर चुप क्यों?

> उत्तर प्रदेश में स्कूलों में 21.83 लाख नामांकन पिछले साल की तुलना में कम हुए, जबकि बिहार में 6.14 लाख, राजस्थान में 5.63 लाख और पश्चिम बंगाल 4.01 लाख नामांकन कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मील कवरेज में 5.41 लाख छात्रों की कमी आई।

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक बार फिर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने महिलाओं और छात्राओं को चेतावनी दी कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। पटेल का कहना है कि दूर रहें, वरना आप 50 टुकड़ों में मिलेंगी। यह टिप्पणी उनके पिछले दावे के ठीक अगले दिन आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि लिव-इन रिलेशनशिप का असर देखने के लिए किसी अनाथालय में जाना चाहिए, जहाँ 15 साल की लड़कियाँ अपने बच्चों के साथ कतार में खड़ी होती हैं। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों और न्यायाधीशों के साथ बैठक में भी छात्रों को लिव-इन रिलेशनशिप से बचाने के उपाय सुझाए थे।

राज्यपाल पटेल का यह बयान निश्चित तौर पर युवतियों को जागरुक करने वाला और लिव इन रिलेशनशिप के खतरों से आगाह करने वाला है। सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश की युवतियों और महिलाओं के समक्ष यही एक खतरा है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने महिलाओं से जुड़े सिर्फ एक खतरे के सावचेत रहने की सीख दी है। लिव इन रिलेशनशिप के नकारात्मक पहलू हैं जरूर, लेकिन इस चलन अभी व्यापक रूप से नहीं है। महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश में महिलाओं से जुड़े अन्य खतरों को अनदेखा कर गई, क्योंकि शायद वहां भाजपा की सरकार है। अन्य

खतरे लिव इन रिलेनशिप से कहीं ज्यादा गंभीर है। इनका निदान भी सरकार के लिए आसान नहीं है। राज्यपाल ने कभी इन खतरों का जिक्र तक नहीं किया।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,48,211 मामले दर्ज किए गए। इनमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 66,381 मामले, उसके बाद महाराष्ट्र में 47,101 और राजस्थान में 45,450 मामले दर्ज किए गए। इन तीनों राज्यों में से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 में भी भाजपा की सरकारें थी। ऐसे में भाजपा महिला अपराधों की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। महिलाओं से जुड़े साइबर अपराधों में लखनऊ का देश में चौथा स्थान है, जिसमें अश्लील फोटो-वीडियो और फेक कंटेंट जैसे मामले शामिल हैं। इस श्रेणी में लखनऊ से आगे बैंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली हैं।

उत्तर प्रदेश जहां महिला अपराधों में अग्रणी है, वहीं महिलाओं और बच्चों के अन्य मामलों में पिछड़ा हुआ है। देश के 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 63 जिलों में 50 फीसदी से अधिक बच्चे आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं और कुपोषित पाए गए हैं, जिनमें से 34 जिले अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जून 2025 के पोषण ट्रैकर के अनुसार महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम के कुछ जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 34 जिले ऐसे हैं जहां बच्चों में कुपोषण की दर 50 फीसदी से अधिक है। इसके बाद मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और असम का स्थान है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट (2024-25) के अनुसार, विगत वर्षों में सुधार के बावजूद उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक बाल मृत्यु दर वाले राज्यों में शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 1,000 बच्चों में से 43 बच्चे अपने पाँचवें जन्मदिन से पहले मर जाते हैं। वर्तमान शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 1,000 जीवित जन्मों पर 38 है, जबकि नवजात मृत्यु दर(आईएमआर) 28 है। यूनिसेफ इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार लगभग 46% मातृ मृत्यु और 40% नवजात मृत्यु प्रसव के दौरान या जन्म के बाद पहले 24 घंटों के भीतर हो जाती हैं।

उत्तर प्रदेश में स्कूलों में 21.83 लाख नामांकन पिछले साल की तुलना में कम हुए, जबकि बिहार में 6.14 लाख, राजस्थान में 5.63 लाख और पश्चिम बंगाल 4.01 लाख नामांकन कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मील कवरेज में 5.41 लाख छात्रों की कमी आई। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यूडीआइएसई) की वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 18 प्रतिशत सरकारी स्कूलों, अर्थात लगभग 27,000 स्कूलों के भवन जर्जर स्थिति में हैं। इनमें से कई स्कूलों की छतें और दीवारें ख़तरनाक स्थिति में हैं। लखनऊ में प्राथमिक विद्यालय और नसीराबाद में छत का प्लास्टर गिरने से दो बच्चे घायल हो गये। नोएडा और गोरखपुर के इलाक़ों से भी ऐसी ही घटनाएँ सामने आ चुकी हैं।

एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन (एएसईआर) 2024 की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश के 22 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में कार्यशील शौचालय ही उपलब्ध नहीं हैं और 35 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं हैं। लगभग 40 प्रतिशत विद्यालयों में तो नियमित स्वच्छता व्यवस्था ही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या और गम्भीर है, जहाँ शौचालयों की कमी के कारण लड़कियों की ड्रॉपआउट दर में 10-12 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी है। शिक्षा मंत्रालय की 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 28 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में पेयजल की सुविधा नहीं है और 40 प्रतिशत स्कूलों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। आश्चर्य यह है कि राज्यपाल आनंदी बेन ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों से जुड़े इन मुद्दों का कभी जिक्र तक नहीं किया। बेहतर होता कि जिस तरह राज्यपाल पटेल ने लिव इन रिलेशनशिप से युवतियों को आगाह किया, उसी तरह योगी सरकार को भी आगाह करती तो शायद उत्तर प्रदेश में महिलाओं की मौजूदा हालत बेहतर हो सकती थी।

सरोकार

झाड़ू की साधना : एक दिवाली पूर्व आत्मकथा

दिवाली आने वाली थी। घर में सफाई का हंगामा मचा हुआ था। दीवारों से लेकर खिड़कियों तक हर कोना जैसे अपने अस्तित्व पर प्रश्न उठा रहा था कि आखिर इतने सालों से हम पर इतनी धूल क्यों जमने दी गई! ऐसे ही समय में मेरे हाथों में झाड़ू आ पड़ी। वह झाड़ू, जो अब तक रानी के हाथों में शोभा देती थी, इस बार मेरे हाथों में आकर मानो अपने पुराने स्वामी को खोने का दुख सुना रही थी। रानी... वह सिर्फ नौकरानी नहीं थी, घर की आत्मा थी। उसके हाथों से घर में जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा फैल जाती थी। बर्तन बजते तो संगीत लगता, झाड़ू चलती तो हवा में लय दौड़ती, और जब वह कपड़े सुखाती थी तो लगता जैसे धूप भी मुस्कुरा उठी हो। रानी के ससुराल जाते ही घर की रौनक जैसे साथ ही चली गई। पत्नी की आंखों में हल्की सी नाराज़गी थी — "अब खुद ही करना पड़ेगा सब।" और फिर एक दिन, जैसे किसी शत्रु का शस्त्र हाथ में थमा दिया जाता है, वैसे ही झाड़ू मेरे हाथ में आ गई।

पहले तो मैंने उसे शत्रु ही माना। घर के हर कोने में दुश्मन छिपे थे — मकड़ी, छिपकली, कॉकरोच, और वो भी ऐसी जगहों पर जहां पहुंचना किसी गुफा में उतरने जैसा लगता था। जब-जब झाड़ू उन पर प्रहार करती, पत्नी की आवाज़ पीछे से आती — "सावधान! झाड़ू मत तोड़ देना। महंगाई का जमाना है।" झाड़ू टूटने का अपराध जैसे देशद्रोह से कम नहीं था। मैं सोचने लगा, "हे रानी, तू यह सब कैसे झेल लेती थी?"

बचपन में झाड़ू का चेहरा कुछ और था। वह जादूगरनी की उड़न-सवारी थी। परियों की कहानियों में झाड़ू पर बैठी कोई बुढ़िया आसमान में उड़ा करती थी। मैं उस समय सोचता था कि झाड़ू में जरूर कोई रहस्यमय शक्ति होती होगी जो इंसान को आकाश तक पहुंचा देती है। लेकिन अब समझ में आया — झाड़ू सचमुच उड़ा देती है, पर उड़ान आसमान की नहीं, अहंकार की होती है। वह हमें अपने नीचे झुकना सिखाती है।

एक दिन जब मैं झाड़ू चला रहा था, तो अनायास ध्यान गया कि झाड़ू के तिनके कितने अनुशासित होते हैं। वे सब एक डोरी में बंधे रहते हैं, कोई आगे नहीं निकलता, कोई अलग नहीं झांकता। सब मिलकर धूल हटाते हैं। जैसे समाज को साफ करने के लिए भी ऐसे ही 'तिनकों' का संगठन चाहिए — बिना अहंकार, बिना प्रसिद्धि की चाह। फिर ध्यान आया, वही झाड़ू जब किसी राजनेता के हाथ में आती है, तो अचानक उसका अर्थ बदल जाता है। अब वह 'सफाई' नहीं, 'अभियान' कहलाती है। कैमरे की फ्लैश चमकती है, भीड़ तालियां बजाती है, और कुछ सेकंड बाद वही झाड़ू किसी कोने में धूल खा रही होती है। मुझे लगा कि असली सफाई झाड़ू से नहीं, इरादे से होती है। रानी के इरादे साफ थे, इसलिए घर चमकता था। नेताओं के इरादे गंदे हैं, इसलिए देश धूल-धूसरित है। और हमारे इरादे आलसी हैं, इसलिए हम अपने ही घर की गंदगी में बैठे शिकायत करते हैं।

धीरे-धीरे यह झाड़ू मेरे लिए ध्यान की वस्तु बन गई। जब मैं झुककर फर्श बुहारता, तो भीतर कोई और सफाई होती महसूस होती। पुराने अहंकार, बीते दुःख, भूले-बिसरे ग़ुरूर जैसे धूल बनकर उड़ जाते। लगा, शायद दिवाली का असली अर्थ यही है — बाहर की नहीं, भीतर की सफाई। घर में दीपक तो बाद में जलते हैं, पहले मन की कालिख उतरनी चाहिए।

रानी अब कभी-कभी मिलने आती है। साड़ी में लिपटी, माथे पर सिंदूर, चेहरा पहले से अधिक शांत। वह मुस्कुराकर पूछती है — "भैया, घर चमकता है न?" मैं कहता हूं — "अब तो भीतर भी थोड़ा चमकने लगा है।" वह हंस देती है, और मुझे लगता है जैसे झाड़ू के तिनके फिर झनझना उठे हों।

अब मैं झाड़ू को साधन नहीं, साधना मानता हूं। यह मेरी विनम्रता की तपस्या है। जब हाथ में झाड़ू होती है, तो लगता है जैसे मैं भी उसी धरती का एक तिनका हूं — छोटा, पर उपयोगी। दिवाली की सफाई अब कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक आत्मिक अभ्यास है।

कभी-कभी मैं सोचता हूं, जो लोग राजमहलों में रहते हैं, क्या उन्होंने कभी अपने हाथों से झाड़ू चलाई होगी? शायद नहीं। तभी तो उनके मनों पर धूल जमी रहती है। वे बाहर सोना चमकाते हैं, भीतर अंधेरा रखते हैं। और मैं, जो अपने छोटे से घर में झाड़ू चलाता हूं, महसूस करता हूं कि भीतर कहीं दीपक जल उठा है।

इसलिए आज जब मैं दरवाजे बंद करके झाड़ू चलाता हूं, तो न पत्नी की फटकार सुनाई देती है, न थकान का बोझ। बस लगता है जैसे कोई पुरानी प्रार्थना दोहराई जा रही हो — "हे स्वच्छता देवी, बाहरी ही नहीं, भीतरी धूल भी बुहार दो।" झाड़ू के हर तिनके के संग एक मंत्र निकलता है — नमो विनम्राय, नमो स्वच्छाय, नमो प्रकाशाय।

और तब मुझे सच में महसूस होता है — उम्र के इस पड़ाव पर हाथ में झाड़ू आना कोई शर्म नहीं, बल्कि सम्मान है। यह उस जीवन की निशानी है जो भीतर से झुकना और बाहर से चमकना जानता है। रानी की दी हुई सीख अब मेरे हाथ की झाड़ू में बस गई है, और हर बुहारी में मैं उसे प्रणाम करता हूं।

दिवाली के दीपक जलेंगे, मिठाइयाँ बटेंगी, नए कपड़े पहनेंगे — पर मेरे लिए इस बार सबसे बड़ा उत्सव वही होगा, जब झाड़ू चलेगी, और मन से एक और परत की धूल उठकर उड़ जाएगी।

समृद्ध का एहसास कराता है धनतेरस

धनतेरस का त्योहार दीपावली पर्व के प्रारम्भ को दर्शाता करता है। धनतेरस पूजा को धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस के दिन नई वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। यह त्योहार लोगों के जीवन में समृद्धि और स्वास्थ्य लाने के लिए माना जाता है और इसलिए इसे बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। अगर सम्भव न हो तो कोई बर्तन खरीदे। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चन्द्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है और मन में सन्तोष रूपी धन का वास होता है। धनतेरस का दिन धन्वन्तरी त्रयोदशी या धन्वन्तरि जयन्ती भी होती है। धनतेरस को आयुर्वेद के देवता का जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन गणेश लक्ष्मी घर लाएं जाते है। इस दिन लक्ष्मी और कुबेर की पूजा के साथ-साथ यमराज की भी पूजा की जाती है। पूरे वर्ष में एक मात्र यही वह दिन है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। यह पूजा दिन में नहीं की जाती अपितु रात्रि होते समय यमराज के निमित्त एक दीपक जलाया जाता है।

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दौरान अपने घर में 13 दीये जलाना चाहिए और अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जिसमें से सबसे पहले दक्षिण दिशा में यम देवता के लिए और दूसरा धन की देवी मां लक्ष्मी के लिए जलाना चाहिए। इसी तरह दो दीये अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीया तुलसी महारानी के लिए एक दीया घर की छत पर और बाकी दीये घर के अलग-अलग कोने में रख देने चाहिए। माना जाता है कि यह 13 दीये नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं से रक्षा करते हैं।

धनतेरस के दिन यमराज को प्रसन्न करने के लिए यमुना स्नान भी किया जाता है अथवा यदि यमुना स्नान सम्भव न हो तो स्नान करते समय यमुना जी का स्मारण मात्र कर लेने से भी यमराज प्रसन्न होते हैं। हिन्दु धर्म की ऐसी मान्यता है कि यमराज और देवी यमुना दोनों ही सूर्य की सन्ताने होने से आपस में भाई-बहिन हैं और दोनों में बड़ा प्रेम है। इसलिए यमराज यमुना का स्नान करके दीपदान करने वालों से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते और उन्हें अकाल मृत्यु के दोष से मुक्त कर देते है।

धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस दिन का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा है कि जिन परिवारों में धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है। वहां अकाल मृत्यु नहीं होती। घरों में दीपावली की सजावट भी इसी दिन से प्रारम्भ होती है। इस दिन घरों को लीप-पोतकर, चौक में रंगोली बनाकर सायंकाल के समय दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का आवाहन किया जाता है। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलना व नए बर्तन खरीदना शुभ माना गया है। धनतेरस को चांदी के बर्तन खरीदने से तो अत्यधिक पुण्य लाभ होता है। इस दिन कार्तिक स्नान करके प्रदोष काल में घाट, गौशाला, कुआं, बावड़ी, मंदिर आदि स्थानों पर तीन दिन तक दीपक जलाना चाहिए।

धनतेरस के दिन यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता हैं। इस दीप को यमदीवा अर्थात यमराज का दीपक कहा जाता है। रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डालकर नई रूई की बत्ती बनाकर, चार बत्तियां जलाती हैं। दीपक की बत्ती दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए। जल, रोली, फूल, चावल, गुड़, नैवेद्य आदि सहित दीपक जलाकर स्त्रियां यम का पूजन करती हैं। चूंकि यह दीपक मृत्यु के नियन्त्रक देव यमराज के निमित्त जलाया जाता है, अतः दीप जलाते समय पूर्ण श्रद्धा से उन्हें नमन तो करें। साथ ही यह भी प्रार्थना करें कि वे आपके परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखें और किसी की अकाल मृत्यु न हो। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है।

धनतेरस को मृत्यु के देवता यमराज जी की पूजा करने के लिए संध्या के समय एक वेदी (पाट्टा) पर रोली से स्वास्तिक बनाइये। उस स्वास्तिक पर एक दीपक रखकर उसे प्रज्वलित करें और उसमें एक छिद्रयुक्त कोड़ी डाल दें। अब इस दीपक के चारों ओर तीन बार गंगा जल छिडकें। दीपक को रोली से तिलक लगाकर अक्षत और मिष्ठान आदि चढाएं। इसके बाद इसमें कुछ दक्षिणा आदि रख दीजिए जिसे बाद में किसी ब्राह्मण को दे देवें। अब दीपक पर कुछ पुष्पादि अर्पण करें। इसके बाद हाथ जोडकर दीपक को प्रणाम करें और परिवार के प्रत्येक सदस्य को तिलक लगाएं। अब इस दीपक को अपने मुख्य द्वार के दाहिनी और रख दीजिए। यम पूजन करने के बाद अन्त में धनवंतरी पूजा करें।

इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। दैव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुण्डली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक चार दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा।

नजरिया

धनतेरस का सच्चा रहस्य : क्या खरीदें, क्या नहीं, और क्यों

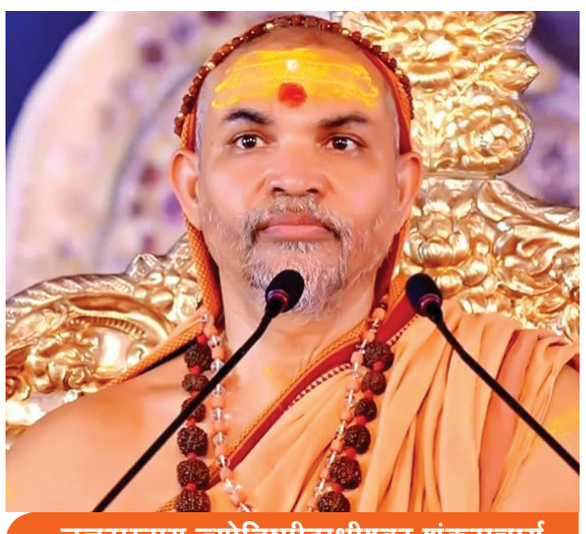

उत्तराम्नाय ज्योतिष्पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

धनतेरस का दिन केवल खरीदारी का अवसर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा परिवर्तन का क्षण है। दीपावली से दो दिन पहले जब पूरे वातावरण में शुद्धि और उत्साह का संचार होता है, तब यह दिन हमें केवल वस्तुएं खरीदने नहीं, बल्कि अपने कर्म, विचार और घर की तरंगों को शुद्ध करने का भी अवसर देता है। किंतु अनेक बार हम परंपरा की गहराई को जाने बिना ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं जो शुभता की जगह अशुभता को बुला लेती हैं।

कहा जाता है कि धनतेरस का उद्गम उस क्षण से जुड़ा है जब समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरि देवता अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उस क्षण में अमृत का प्रतीक था—जीवन, स्वास्थ्य और दीर्घायु। इसीलिए यह दिन केवल "धन" का नहीं, बल्कि धन्य जीवन का पर्व है। परंतु जब मनुष्य धन के पीछे केवल भौतिक अर्थ में दौड़ने लगता है, तब वही शुभ दिन उसके लिए बाधा बन जाता है।

धनतेरस के दिन लोहे की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लोहा शनि का धातु है—शक्ति तो रखता है पर उसका स्वभाव 'रोकने' और 'भारी करने' का होता है। इस दिन यदि हम लोहे की वस्तुएं लाते हैं, तो वह शुभता की प्रवाहमान ऊर्जा को भारी बना देता है। इसलिए सोना, चांदी, तांबा या पीतल जैसी धातुएं शुभ मानी गई हैं, क्योंकि वे सूर्य और बृहस्पति की सकारात्मक तरंगें अपने भीतर रखती हैं।

काले रंग की वस्तुएं भी इसी कारण वर्जित कही गई हैं। काला रंग ब्रह्मांड की ऊर्जा को सोख लेता है, जबकि इस दिन हमें अपने घर में प्रकाश और विस्तार चाहिए। धनतेरस का पूरा भाव है प्रकाश की ओर गमन—अंधकार से नहीं, उजाले से संवाद। जो व्यक्ति इस दिन काले कपड़े या सजावटी वस्तुएं खरीदता है, वह अनजाने में उसी अंधकार को अपने घर का अतिथि बना लेता है जिससे बचना चाहिए।

पुराने सिक्के या इस्तेमाल की गई प्रतिमाएं भी अशुभ मानी जाती हैं क्योंकि उनमें दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा छाप होती है। हर वस्तु अपनी तरंग रखती है, और जब हम किसी दूसरे की ऊर्जा को अपने घर बुला लेते हैं, तो वह हमारे घर की समरसता को प्रभावित करती है। इसीलिए इस दिन नए सिक्के, नई लक्ष्मी-गणेश प्रतिमाएं खरीदना ही वास्तविक शुभ कर्म है।

कांच की वस्तुएं भी वास्तुशास्त्र के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। कांच में स्थायित्व नहीं होता, वह नाजुक और अस्थिर होता है। जबकि लक्ष्मी का अर्थ है स्थायित्व, सौम्यता और गरिमा। इसलिए धनतेरस पर कांच के बजाय धातु की चीजें खरीदनी चाहिए — क्योंकि धातु पृथ्वी तत्व से जुड़ी है, जो स्थिरता और समृद्धि का मूल है।

अब बात झाड़ू की — झाड़ू धनतेरस के दिन एक विशेष प्रतीक है। यह मां लक्ष्मी का प्रतीक इसलिए माना गया है क्योंकि झाड़ू से हम न केवल घर की धूल, बल्कि जीवन की नकारात्मकता को भी बुहारते हैं। परंतु इसकी खरीद का समय और स्थिति बेहद सूक्ष्म होती है। शाम के समय झाड़ू खरीदना या प्लास्टिक की झाड़ू लेना अशुभ माना गया है। कारण यह कि सूर्यास्त के बाद पृथ्वी की ऊर्जाएं बदलती हैं और उस समय नई वस्तुओं का ग्रहण 'स्थायी लाभ' नहीं देता। झाड़ू केवल प्राकृतिक तिनकों की बनी होनी चाहिए, क्योंकि वही धरती की सत्व-ऊर्जा को अपने में रखती है।

धनतेरस के दिन कर्ज लेकर खरीदारी करना भी निषेध बताया गया है। यह केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि कर्म सिद्धांत से जुड़ा है। जब हम ऋण लेकर उत्सव मनाते हैं, तो ब्रह्मांड में एक "ऋण-ऊर्जा" का बीज बो देते हैं। फिर वही ऊर्जा भविष्य में बार-बार कर्ज के रूप में लौटती है। इसीलिए कहा गया है — "जिसके पास जितना है, उसी में संतोष रखो, वही असली लक्ष्मी की कृपा है।"

धनतेरस का वास्तविक अर्थ यह नहीं कि आप हर वस्तु खरीदें — बल्कि यह है कि जो वस्तु खरीदें, वह नए आरंभ का प्रतीक हो। सोना-चांदी इसलिए शुभ हैं क्योंकि वे सूर्य और चंद्र की ऊर्जा का संगम हैं — एक गर्मी देता है, दूसरा शीतलता; एक क्रिया है, दूसरा करुणा। इन्हीं के बीच सृष्टि का संतुलन है।

मालिक जयेश जग्शी गाला हेतु प्रकाशक, मुद्रक **अश्विनी कुमार दुबे** द्वारा मोदी प्रिंटर्स, 24 बोमनजी लेन, फोर्ट, मुंबई-400001 (महाराष्ट्र) से मुद्रित कर महाराष्ट्र ग्रेन स्टोर्स, 28, डॉ. भगवानदास इंद्रजीत रोड, वालकेश्वर, मलबार हिल, मुंबई-400006 से प्रकाशित किया।
संपादकः **अश्विनी कुमार दुबे** (पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी है, न्याय क्षेत्र मुंबई) कार्यकारी संपादकः अरविंद मिश्रा, सहसंपादकः सुजीत मिश्रा ('दै.'राष्ट्रीय स्वाभिमान 'में सभी लोग सहयोगात्मक और अवैतनिक तौर पर कार्यरत हैं)
● आर.एन.आई.:MAHHIN/2008/24084 ● ईमेलः rastriyaswabhiman@gmail.com ● भ्रमणध्वनि क्र. +919224733113

संक्षिप्त समाचार

महिला कांग्रेस महाराष्ट्र इकाई में नई कमेटी और जिला अध्यक्षों की घोषणा, थाने और भिवंडी के लिए प्रमुख नाम शामिल

ALL INDIA MAHILA CONGRESS

ALKA LAMBA
PRESIDENT

24, Akbar Road,
New Delhi-110011

District Presidents			
1.	Arti Doibale	District President	Nanded South
2.	Aruna Prabhakar Dhote	District President	Wardha City
3.	Dipali Lalaji Misal	District President	Aurangabad City
4.	Swati Mahesh Shinde	District President	Pune City
5.	Adv. Kunda Avinash Jenekar	District President	Chandrapur Rural
6.	Kavita Moharkar	District President	Gadchiroli
7.	Swati Rajesh Jadhav	District President	Nashik
8.	Saakshi S Vanjari	District President	Sindhudurg
9.	Sayali Kiran Nadhe	District President	Chinchvad City
10.	Janhavi Deshmukh	District President	Thane Rural
11.	Kanchan Kulkarni	District President	Kalyan
12.	Vandana Purushottam Awari	District President	Yavatmal
13.	Sushma Sharadchandra Rajeghorpade	District President	Satara
14.	Rehana Helal Ansari	District President	Bhiwandi
15.	Roopa Pinto	District President	Mira Road
16.	Chanda Manojrao Wairagade	District President	Chandrapur City
17.	Pravina Ramakant Chaudhari	District President	Vasai Virar
18.	Jayshree Ravindra Borkar	District President	Bhandara
19.	Vandana Raju Kale	District President	Gondia
20.	Jayshree Wankhade	District President	Amravati City
21.	Smita Sachin Vaity	District President	Thane City
22.	Seema Potdar	District President	Palghar
23.	Rekha Gharat	District President	Raigarh

(Alka Lamba)

ALL INDIA MAHILA CONGRESS

ALKA LAMBA
PRESIDENT

24, Akbar Road,
New Delhi-110011

17th October 2025

Subject: Maharashtra Pradesh Mahila Congress New Executive Committee & District Presidents

This is to inform that a new State Executive Committee & some District Presidents have been constituted. This decision has been taken to further strengthen the organization.

The details of the newly appointed State Executive Committee & District Presidents of Maharashtra Pradesh Mahila Congress are as follows:

Sr. No.	Name	Designation	District Name
	State Executive Committee		
1.	Sandhya Sawwlakhe	State President	Yavatmal
2.	Shailaja Prakashbapu Patil	Member Advisory Committee	Sangli
3.	Sunita Gawande	Member Advisory Committee	Nagpur
4.	Hemlata Meghe	Vice-President	Wardha
5.	Anita Bhandari	General Secretary	Aurangabad
6.	Archana Rajendra Bhomle	General Secretary	Wardha
7.	Sangeeta Tiwari	General Secretary	Pune
8.	Sunanda Dilip Dhobe	General Secretary	Chandrapur
9.	Adv Maneesha C Rote	General Secretary	Sangli
10.	Dr Anjali P Thakare	General Secretary	Amravati
11.	Seema Vinod Sahare	General Secretary	Chandrapur
12.	Seema Mahesh Ahuja	General Secretary	Thane
13.	Ujwalaa Salve	General Secretary	Thane
14.	Rina Gulshan Khandekar	General Secretary	Bhiwandi
15.	Pratima Uke	General Secretary	Nagpur
16.	Chandrakala Naidu	General Secretary	Navi Mumbai
17.	Anita Rohitkumar Prajapati - Jadhav	General Secretary	Thane
18.	Vaishali Pandurang Patio	Secretary	Kolahapur
19.	Bharti Shantaram Jalgaonkar	Secretary	Panvel
20.	Archana Abhijeet Shah	Secretary	Pune
21.	Romina M. Monitero	Secretary	Amravati
22.	Humaira Khan	Secretary	Thane
23.	Rukhsana Qureshi	Secretary	Bhiwandi
24.	Shilpa Gangadhar Sonone	Secretary	Thane

नई दिल्ली/मुंबई : ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अल्का लाम्बा ने महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी समिति और कुछ जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य संगठन को और मजबूत बनाना और विभिन्न जिलों में सक्रिय नेतृत्व स्थापित करना बताया गया है।

नई सूची में थाने, भिवंडी, कुल्याण, वसई-विरार, पालघर, मीरारोड सहित महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। थाने जिले के लिए स्मिता सचिन वैटी, भिवंडी जिले के लिए रेहाना हिलाल अंसारी, और वसई-विरार के लिए प्रवीणा रामाकांत चौधरी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है।

साथ ही, नई स्टेट एक्ज़िक्यूटिव कमेटी में विभिन्न जिलों से कई नेताओं को जनरल सेक्रेटरी, वाइस-प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी पदों पर शामिल किया गया है। थाने जिले से सीमा महेश आहूजा, उज्वला साळवे, अनिता रोहितकुमार प्रजापति-जाधव और शिल्पा गंगाधर सोनोने को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि भिवंडी जिले से रीना गुलशन खंडेकर और रुखसाना कुरैशी को शामिल किया गया है।

महिला कांग्रेस ने यह कदम राज्य स्तर पर संगठन की सुदृढ़ता, जिला नेतृत्व की सक्रियता और महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। इस नई टीम के गठन से आगामी चुनावी तैयारियों और सामाजिक कार्यों में और अधिक प्रभावी नेतृत्व की उम्मीद जताई जा रही है।

अहमदनगर ने खोया एक सच्चा जननेता: भाजपा विधायक शिवाजीराव कर्डीले का निधन, पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर

अहमदनगर। राजनीति के उस युग में जब वादों से ज़्यादा दिखावे का बोलबाला है, वहीं एक ऐसा नेता आज इस दुनिया से विदा हो गया, जिसकी पहचान थी उसकी सादगी, सेवा और सत्यनिष्ठा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राहुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिवाजीराव भानुदास कर्डीले का शुक्रवार सुबह आकस्मिक निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे। बताया जाता है कि सुबह लगभग सात बजे उन्हें घर पर अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। परिवारजन उन्हें तत्काल अहमदनगर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डीले कुछ समय पहले गंभीर बीमारी से उबरकर धीरे-धीरे स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। उनके निधन की खबर ने जैसे पूरे अहमदनगर को स्तब्ध कर दिया। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि वह नेता, जो हर समय जनता के बीच मुस्कुराते हुए मिलता था, अब हमेशा के लिए मौन हो गया।शिवाजीराव कर्डीले का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें परिश्रम और ईमानदारी का गुण था। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक साधारण दूध व्यवसायी के रूप में की, लेकिन उनके भीतर समाज के लिए कुछ करने की ललक थी। गांव में लोगों की समस्याएं सुनना, उनकी मदद करना, यही उनका जीवन का उद्देश्य बन गया। इसी भावना ने उन्हें गांव बुर्हानगर का सरपंच बनाया, और यहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई।

ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान रहें; क्लिक करने से पहले सोचें कोपरी पुलिस का जनजागरूकता संदेश

ठाणे। आज के डिजिटल युग में मोबाइल और इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। लेकिन इसी सुविधा के साथ अपराध का एक नया रूप — साइबर अपराध — तेजी से बढ़ रहा है। एक गलत क्लिक या लापरवाही से साझा किया गया संदेश किसी व्यक्ति को आर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से भारी नुकसान पहुँचा सकता है।

युवा पीढ़ी को इन खतरों से सचेत करने के उद्देश्य से कोपरी पुलिस स्टेशन द्वारा पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी जूनियर कॉलेज और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में एक विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

ठाणे पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे के आदेशानुसार, 4 से 31 अक्टूबर तक पूरे शहर में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से छात्रों को साइबर अपराधों की प्रकृति, बढ़ते मामलों और उनसे बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक निशिकांत विश्वकर के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को बताया कि साइबर अपराधी अब आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग कर लोगों को अपने जाल में फँसाने लगे हैं।

उन्होंने सलाह दी कि—

बैंक, आधार, सरकारी योजनाओं या लॉटरी के नाम पर आने वाले किसी भी लिंक पर क्लिक न करें।

ओटीपी, कार्ड नंबर या व्यक्तिगत जानकारी किसी को न दें।

कोई संदिग्ध कॉल, संदेश या ईमेल मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।

कार्यक्रम में छात्रों को नए बीएनएस और बीएनएसएस कानूनों के साथ-साथ 'गुड टच-बैड टच' जैसे विषयों पर भी संवेदनशील और उपयोगी जानकारी दी गई।

पुलिस अधिकारियों ने कहा, "शारीरिक, मानसिक या ऑनलाइन उत्पीड़न की किसी भी घटना की सूचना तुरंत माता-पिता या पुलिस को दें। चुप्पी कोई समाधान नहीं है — समय पर चेतावनी भविष्य में बड़े खतरे को रोक सकती है।"

इसके अलावा, छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया गया। पुलिस ने कहा, "नशा न केवल शरीर को नष्ट करता है, बल्कि जीवन की दिशा भी बदल देता है। एक गलत निर्णय पूरे भविष्य को बर्बाद कर सकता है।"

कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने साइबर सुरक्षा से संबंधित कई प्रश्न पूछे —

जैसे "अपनी जानकारी कैसे सुरक्षित रखें?", "फर्जी प्रोफाइल की पहचान कैसे करें?", "ऑनलाइन धोखाधड़ी होने पर शिकायत कहाँ करें?"

पुलिस ने इन सभी सवालों के व्यावहारिक उदाहरणों के साथ उत्तर दिए।

इस पहल में पुलिस उप-निरीक्षक राजेंद्र किंगरे, सीताराम गावित और स्वप्निल सोबले ने विशेष भूमिका निभाई।

अंत में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक निशिकांत विश्वकर ने कहा, "छात्रों के लिए डिजिटल दुनिया सुविधाजनक तो है, लेकिन खतरनाक भी हो सकती है। इसलिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और धोखाधड़ी से खुद को बचाएँ।"

गौ की रक्षा की बात हर चुनाव में उठाते रहेंगे: जगद्गुरु शंकराचार्य

सनातन धर्म की रक्षा हेतु बिहार में मतदाता संकल्प यात्रा संपन्न

राष्ट्रीय स्वाभिमान संवाददाता

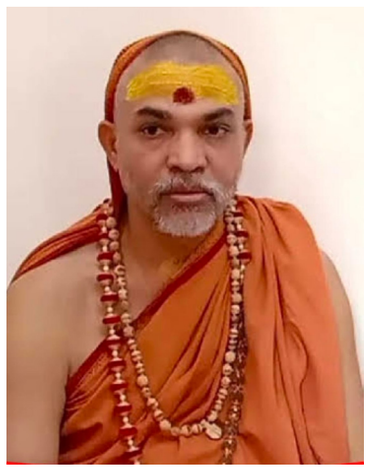

पटना। "चाहे एक ही वोट मिले, पर गौमाता की रक्षा की बात हर चुनाव में उठाते रहेंगे।" यह प्रेरणादायी संदेश जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने बिहार प्रवास के दौरान दिया।

उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की सर्वोच्चता केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं, बल्कि गौमाता और देश की संस्कृति की रक्षा में निहित है। इसी भावना के साथ उन्होंने बिहार के 33 जिलों में मतदाता संकल्प यात्रा पूरी की, जिसका समापन पटना स्थित महावीर हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ हुआ।

जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा, "यह पहली बार है जब सीधे सनातनी मतदाताओं से संवाद स्थापित कर गौमाता की रक्षा और गो-हत्या पर रोक को चुनावी मुद्दा बनाने का संकल्प लिया गया है। यदि शासन और प्रशासन हमारी बात नहीं सुनते, तो अब गौभक्तों को स्वयं आगे बढ़कर चुनाव मैदान में उतरना चाहिए।"

इस अवसर पर चुनाव संचालन समिति की सदस्य डॉ. निशीथा दीक्षित ने बताया कि गुरुदेव का संदेश है कि हर सनातनी मतदाता धर्म, राष्ट्र और गौसेवा के प्रति जागरूक रहे तथा अपने मताधिकार का प्रयोग धर्म के पक्ष में करे।"

जगद्गुरु ने यह भी कहा कि आज की चुनावी प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई है कि सामान्य नागरिक और गौभक्त स्वतंत्र रूप से अपनी उम्मीदवारी दाखिल करने में कठिनाई का सामना करते हैं।

फिर भी अनेक गौसेवक और धर्मनिष्ठ नागरिक इस बार सक्रिय रूप से चुनाव में भाग लेंगे।

अंत में उन्होंने सभी सनातनी मतदाताओं से आह्वान किया, "गौमाता की रक्षा की आवाज हर चुनाव में उठनी चाहिए, यही सच्ची राष्ट्र सेवा और धर्म सेवा है।"

ठाणे सिविल अस्पताल ने नागरिकों से की सावधानी बरतने की अपील

ठाणे। दिवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और एकजुटता का प्रतीक है। लेकिन इस रोशनी के उत्सव में स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। त्योहार के दौरान पटाखों से जलने, सांस लेने में तकलीफ, अपच और दुर्घटनाओं के मामलों में वृद्धि देखी जाती है।

इसी को ध्यान में रखते हुए जिला शल्य चिकित्सक डॉ. कैलाश पवार ने नागरिकों से अपील की है कि, "त्योहार मनाएँ, लेकिन अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति सचेत रहें। दिवाली का असली आनंद तन, मन और समाज तीनों के स्वास्थ्य में है।"

डॉ. पवार ने कहा कि पटाखे भले ही खुशी लाते हैं, लेकिन लापरवाही से वे दुर्घटनाओं, जलन या आँखों में चोट का कारण बन सकते हैं।

उन्होंने बच्चों और बुजुर्गों की विशेष देखभाल की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि अत्यधिक मिठाई खाने से पाचन संबंधी समस्याएँ या मधुमेह के मरीजों में परेशानी बढ़ सकती है।

ठाणे सिविल अस्पताल प्रशासन ने नागरिकों के लिए कुछ आवश्यक निर्देश जारी किए हैं —

-पटाखे जलाते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखें।

-आँखों या त्वचा में चोट लगने पर घरेलू उपचार न करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

-बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा रोगियों को धुएँ और प्रदूषण से दूर रखें।

-संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें और शरीर को हाइड्रेट रखें।

अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि दिवाली का असली प्रकाश स्वास्थ्य का प्रकाश है। ठाणे के शल्य चिकित्सक डॉ. कैलाश पवार ने कहा,"हर नागरिक को त्योहार मनाते समय अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। आइए, हम प्रदूषण-मुक्त, दुर्घटना-मुक्त और स्वस्थ दिवाली मनाएँ।"

ठाणे सिविल अस्पताल ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं और किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों से तुरंत अस्पताल से संपर्क करने की अपील की है।

स्वच्छ भारत अभियान में सभी विभागों के समन्वय से ठाणे मनपा का स्वच्छता अभियान सफल बनाने का संकल्प

ठाणे। ठाणे महानगरपालिका ने स्वच्छ भारत अभियान को प्रभावी और परिणामकारी बनाने के लिए सभी विभागों के समन्वय से कार्य करने का निर्णय लिया है।

मनपा आयुक्त सौरभ राव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग अभी से तैयारी शुरू करें ताकि अगले वर्ष होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में ठाणे शहर का प्रदर्शन सर्वोत्तम हो।

बैठक में अतिरिक्त आयुक्त (1) संदीप मालवी, अतिरिक्त आयुक्त (2) प्रशांत रोडे, नगर अभियंता प्रशांत सोनाग्रा, टीएमटी प्रबंधक भालचंद्र बेहरे, नगर नियोजन के सहायक निदेशक संग्राम कनाडे, सहित सभी उपायुक्त, उपनगर अभियंता, सहायक आयुक्त और कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे।

बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के उपायुक्त मनीष जोशी तथा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रानी शिंदे ने स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी तैयारियों, दिशा-निर्देशों और विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

आयुक्त राव ने कहा कि, "मनपा क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखना हमारा मूल कर्तव्य है। स्वच्छ भारत और माझी वसुंधरा जैसे अभियान न केवल प्रतिस्पर्धा हैं, बल्कि नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का माध्यम भी हैं।"

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि

- दैनिक स्वच्छता कार्य नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण ढंग से हो।
- सार्वजनिक शौचालयों की दिन में चार बार सफाई, आवश्यक मरम्मत और रखरखाव सुनिश्चित किया जाए।
- सड़कें, फुटपाथ, डिवाइडर और पार्क सुव्यवस्थित रखे जाएँ।
- सभी विभाग परस्पर समन्वय के साथ काम करें ताकि शहर की स्वच्छता में सामूहिक सुधार दिखे।

आयुक्त ने आगे कहा कि, "शहर की स्वच्छता प्रत्येक नागरिक के लिए गौरव का विषय बने। मनपा के स्वच्छता दूतों को नागरिकों से निरंतर संपर्क में रहकर उन्हें अभियान से जोड़ना चाहिए।"

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाले आवासीय परिसरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कचरा पृथक्करण और निपटान की नियमित समीक्षा की जाए।

अंत में आयुक्त राव ने कहा कि,"यह अभियान केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। स्वच्छता तभी स्थायी हो सकती है जब हर नागरिक इसे अपनी जिम्मेदारी माने।"

कल्याण स्टेशन पर यात्रियों के लिए अत्याधुनिक वातानुकूलित शौचालय का लोकार्पण

कल्याण। मध्य रेलवे के व्यस्त कल्याण जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन के समीप महालक्ष्मी होटल के सामने बने सार्वजनिक शौचालय का नूतनीकरण कर उसे अत्याधुनिक स्वरूप दिया गया है। शुक्रवार को इसका लोकार्पण कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका के आयुक्त अभिनव गोयल के शुभहस्ते संपन्न हुआ।

इस नवनिर्मित शौचालय का निर्माण और नूतनीकरण जनसेवा लेबर को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, मुंबई द्वारा अपने खर्चे पर किया गया है। संस्था इस वातानुकूलित और आधुनिक प्रसाधनगृह का संचालन 'पे एंड यूज़' प्रणाली पर करेगी।

नए शौचालय में पुरुषों के लिए 9 सीटें, 2 स्नानघर और 6 मूत्रालय, जबकि महिलाओं के लिए 2 सीटें, 1 स्नानघर और एक फीडिंग रूम (स्तनपान कक्ष) की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही महिलाओं के लिए सैनिटरी वेंडिंग मशीन भी लगाई गई है।

सुव्यवस्थित रखरखाव के लिए परिसर में ही केयरटेकर रूम बनाया गया है। सेवा शुल्क क्रमशः मूत्रालय के लिए 2, शौचालय के लिए 7 और स्नानगृह के लिए 20 निर्धारित किया गया है।

लोकार्पण अवसर पर आयुक्त अभिनव गोयल ने कहा कि, "महानगरपालिका का लक्ष्य नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाएँ प्रदान करना है। यह शौचालय उसी दिशा में एक सराहनीय पहल है।"

टोरेंट पावर केवल फ्रेंचाइजी कंपनी है, एमएसईबी द्वारा निर्धारित बिजली दरें ही लागू करती है: चेतन बदियानी

बिजली दर वृद्धि के विरोध में धड़ाकेबाज युवा प्रतिष्ठान काजोरदारआंदोलन

दिवा/ठाणे। दीपावली के पावन अवसर पर कलवा-मुंब्रा-दिवा क्षेत्र के नागरिकों के लिए राहत की खबर है। धड़ाकेबाज युवा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष अमोल धनराज केन्द्रे के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन के बाद टोरंट पॉवर कंपनी ने यह आश्वासन दिया है कि दिवाली के दौरान किसी भी नागरिक की बिजली आपूर्ति नहीं काटी जाएगी।

हाल ही में टोरंट पॉवर ने देढ़ रुपए प्रति यूनिट की दर वृद्धि की घोषणा की थी, जिससे आम नागरिकों में भारी नाराजगी देखी जा रही थी।

अमोल केन्द्रे ने इस अन्यायपूर्ण वृद्धि को रद्द करने की मांग करते हुए ठाणे, भिवंडी और कल्याण के जनप्रतिनिधियों

से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने पहले कल्याण लोकसभा के सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे से मुलाकात की, जिन्होंने आंदोलन करने की सलाह दी।

इसके बाद भिवंडी के सांसद बाल्या मामा म्हात्रे से मुलाकात में उन्होंने अगले महीने आंदोलन का समर्थन करने की बात कही। जबकि ठाणे के सांसद नरेश मस्के ने दीवा क्षेत्र में अवैध बांधकाम बंद करने पर जोर दिया। अमोल केन्द्रे ने कहा, "आखिर आम जनता टोरंट की मनमानी और धोखाधड़ी के खिलाफ न्याय किससे मांगे? कलवा-मुंब्रा-दिवा के नागरिक वर्षों से महंगे बिलों और मनमाने शुल्कों से परेशान हैं। बिल भरने में थोड़ी देरी पर बिजली काट दी जाती है और दोबारा जोड़ने के लिए 210 रुपए अतिरिक्त वसूले जाते हैं — यह पूरी तरह अन्याय है।"

इस मुद्दे पर टोरंट पॉवर के अधिकारी शशिकांत कोटकर ने कहा कि वे इस विषय पर वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्ताव रखेंगे, ताकि राज्य स्तर पर समाधान निकाला जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि, "दिवाली उत्सव के दौरान कलवा, मुंब्रा और दिवा क्षेत्र में किसी भी उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति नहीं काटी जाएगी।" अमोल केन्द्रे के नेतृत्व में यह मोर्चा 17 अक्टूबर की सुबह 10 बजे दिवा में आयोजित किया गया था।

मोर्चे में रामपाल मौर्या, अनिल मौर्या, प्रकाश गावड़े, प्रवीण उतेकर, गजानन शेलार, विनोद कदम, कृष्णा कानडे, संदीप कुशवाह, प्रदीप गुप्ता, कमल गुप्ता, सुमन ससाणे, सरला गायकर, अश्विनी माने, आशा इंगोले, आर.पी. आई. की शीतल बनसोडे और संध्या माने सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

अमोल केन्द्रे ने अंत में कहा, "यह केवल बिजली का मुद्दा नहीं, बल्कि जनता के अधिकार और सम्मान का प्रश्न है। दीपावली अंधेरे की नहीं, उजाले की प्रतीक है — इसलिए किसी भी घर की रोशनी बंद नहीं होनी चाहिए।"

जय श्री राम सेवा संस्था व पीपुल्स सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रेरणादायी उपक्रम, जरूरतमंदों के संग मनाई गई दिवाली

राष्ट्रीय स्वाभिमान । प्रेम चौबे,

वसई (पालघर): "मानवता की सेवा ही सच्ची पूजा है", इसी भावना के साथ जय श्री राम सेवा संस्था और पीपुल्स सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट ने इस वर्ष विक्रमगढ़-जव्हार क्षेत्र में एक अनोखी व प्रेरणादायी दीपावली मनाई।

संस्था के सदस्यों ने विक्रमगढ़ तालुका के आदिवासी क्षेत्रों में जाकर जरूरतमंद परिवारों और छोटे बच्चों के बीच कपड़े, मिष्ठान, नमकीन और खिलौने वितरित किए। दीपों की रोशनी और बच्चों की मुस्कान से पूरा वातावरण भावनाओं और आनंद से भर उठा।

यह संस्था का पहला सामाजिक उपक्रम रहा, जिसमें पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों ने अपने सहयोगियों व परिचितों से सामग्री एकत्रित कर उसे स्नेहपूर्वक पैक कर वंचित बच्चों तक पहुँचाया। वितरण के दौरान टीम का उत्साह, समर्पण और मानवीय संवेदनशीलता सराहनीय रही।

संस्था ने यह संकल्प लिया कि आने वाले सभी प्रमुख त्योहारों पर भी इसी प्रकार समाज के जरूरतमंद वर्गों तक खुशियाँ पहुँचाने का कार्य जारी रहेगा। इस पहल का उद्देश्य केवल वस्तु वितरण नहीं, बल्कि हर चेहरे पर मुस्कान लाना है।

कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारी एवं स्वयंसेवक, सलाहकार विनोद तिवारी, हरिकेश तिवारी, राजू सिंह, एड. सुशील सिंह, अध्यक्ष हितेश दूबे, भाजपा नेता सुनील मिश्रा, कार्यक्रम संयोजक दीपक दूबे, सह संयोजक संदीप सिंह सिंपल, सदस्य मालिक मिश्रा, संतोष पांडे, आशुतोष तिवारी, नागेंद्र यादव, धीरेश उपाध्याय सहित समाज के अनेक गणमान्य लोगों का विशेष सहयोग रहा।

गौमाता राष्ट्रमाता
स्वतःस्फूर्त गौ-प्रतिष्ठा आन्दोलन
Visit : www.1008.guru / Ph. : 7417417414

हिन्दी दैनिक
राष्ट्रीय स्वाभिमान

राष्ट्रीय स्वाभिमान
पत्र व्यवहार:रफ्तार इंडिया एक्सप्रेस, 31/33 पहला महला, पत्रावाला बिल्डिंग, वजु कोटक मार्ग लिंक शहीद भगतसिंह रोड, फोर्ट, मुंबई 400001, भ्र.ध्व. क्र.:9224733113
ईमेल:rastriyaswabhimaan@gmail.com

04 मुंबई, शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 महाराष्ट्र
epaper.rashtriyaswabhimaan.in
www.rashtriyaswabhimaan.com

धारावी से चल रही थी फेक पीएम किसान योजना की ठगी, केरल की महिला से उड़े एक लाख रुपये, यूपी के आज़ाद खान की गिरफ्तारी

मुंबई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) केंद्र सरकार की उन महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जो देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक सहारा प्रदान करती है। लेकिन अब इसी योजना के नाम पर साइबर अपराधियों ने ठगी का नया जाल बिछा दिया है। केरल के अलप्पुझा जिले में एक महिला को इस योजना से जुड़ी फर्जी एपीके (APK) फाइलें डाउनलोड करने के कारण एक लाख रुपये का चूना लग गया। हैरान करने वाली बात यह है कि यह पूरा फर्जीवाड़ा मुंबई के धारावी इलाके से संचालित किया जा रहा था, और पुलिस ने वहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है।

अलप्पुझा पुलिस ने जांच के दौरान धारावी से 42 वर्षीय आज़ाद खान नामक व्यक्ति को पकड़ा है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का निवासी है। पुलिस का मानना है कि यह साइबर ठगी का एक बड़ा नेटवर्क है, जिसमें केवल एक व्यक्ति की संलिप्तता नहीं हो सकती। आरोपी को केरल लाया गया, जहां उसे स्थानीय अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक एम.पी. मोहनचंद्रन ने बताया कि टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस साइबर गैंग में और कौन-कौन शामिल हैं और उनका नेटवर्क किन-किन राज्यों तक फैला हुआ है। अप्रैल महीने में पत्तनक्कड़ पंचायत से जुड़े एक व्हाट्सऐप ग्रुप में "पीएम किसान योजना" के नाम से कुछ APK फाइलें शेयर की गईं। ग्रुप की एक सदस्य महिला, जिसे यह संदेश पूरी तरह भरोसेमंद लगा, ने लिंक पर क्लिक कर फाइल डाउनलोड कर ली। यह फाइल दरअसल एक मैलवेयर (हानिकारक प्रोग्राम) थी, जिसने महिला के फोन से उसकी निजी जानकारी, बैंक डिटेल्स और क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुरा ली। उसी दिन उसके कार्ड का इस्तेमाल फ्लिपकार्ट पर करीब 96,312 रुपये की ऑनलाइन शॉपिंग में किया गया। महिला की शिकायत पर पत्तनक्कड़ थाने के प्रभारी केएएस जयन के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल गठित किया गया, जिसमें जिला साइबर सेल को भी शामिल किया गया। साइबर विशेषज्ञों ने फ्लिपकार्ट से खरीदे गए सामान की जानकारी निकाली, जिससे पता चला कि हैक किए गए कार्ड से पांच मोबाइल फोन खरीदे गए थे। इन मोबाइलों के IMEI नंबर और टॉवर लोकेशन ट्रैक करने पर पाया गया कि वे मुंबई के बांद्रा, सीएसटी और धारावी क्षेत्रों में सक्रिय हैं। मुंबई पुलिस की मदद से टीम ने स्थानीय दुकानों में छापेमारी की, और आखिरकार धारावी की एक मोबाइल दुकान से सुराग मिला।

दुकान के मालिक ने बताया कि मोबाइल फोन आज़ाद खान नामक व्यक्ति ने उसे बेचे थे। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की, तो उसने यह स्वीकार किया कि वह इंटरनेट पर फर्जी सरकारी योजनाओं के नाम से फेक ऐप फाइलें बनाकर लोगों को डाउनलोड लिंक भेजता था, और उनसे डाटा चुराकर ऑनलाइन खरीदारी करता था।

पीड़िता रनिमोल ने बताया कि यह लिंक एक ऐसे व्हाट्सऐप ग्रुप में आया था, जिसका संचालन पंचायत अधिकारी करते हैं। इसलिए उन्होंने उस पर कोई शक नहीं किया। लिंक खोलने के कुछ घंटों बाद ही उनके फोन पर लगातार पांच ओटीपी आए, पर उन्होंने किसी के साथ साझा नहीं किए।

आईआईटी बॉम्बे की नई तकनीक से सैटेलाइट से होगा ग्रीनहाउस गैसों का सटीक आकलन, दिल्ली-मुंबई में प्रदूषण नियंत्रण को मिलेगी नई दिशा

मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती से निपटने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब ग्रीनहाउस गैसों — विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड (CO) और मीथेन (CH) — के स्तर का सटीक आकलन सैटेलाइट तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। यह उपलब्धि आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई एक नई विश्लेषण प्रणाली से संभव हुई है, जो अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को उन्नत गणनाओं के जरिए धरती पर मौजूद वास्तविक प्रदूषण स्तर से जोड़ती है।

इस तकनीक के विकास का श्रेय आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर मनोरंजन साहू और आदर्श अलगडे के नेतृत्व वाली अनुसंधान टीम को जाता है। उन्होंने पाया कि सैटेलाइट से प्राप्त डेटा में यदि उचित एल्गोरिदमिक सुधार और सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाए, तो यह जमीनी निगरानी जितना ही सटीक परिणाम दे सकता है।

भारत में फिलहाल ग्रीनहाउस गैसों की निगरानी के लिए बहुत सीमित संख्या में ग्राउंड-बेस्ड मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, जिससे व्यापक और निरंतर मापना कठिन होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष से प्राप्त डेटा को केंद्र में रखकर एक संपूर्ण निगरानी प्रणाली तैयार की, जिससे अब दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में कार्बन और मीथेन का वितरण क्षेत्रवार और मौसमवार ट्रैक किया जा सकेगा।

इस शोध के तहत वैज्ञानिकों ने "मीथेन हॉटस्पॉट्स" की पहचान भी की — यानी ऐसे क्षेत्र जहां मीथेन गैस का उत्सर्जन अन्य जगहों की तुलना में कहीं अधिक है। अध्ययन में सामने आया कि ये हॉटस्पॉट आमतौर पर लैंडफिल क्षेत्रों, अपशिष्ट जल संयंत्रों और औद्योगिक केंद्रों के आसपास केंद्रित हैं। पिछले कुछ वर्षों में दोनों शहरों में इन गैसों के स्तर में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है, जो भविष्य में जलवायु और स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है। प्रो. साहू का कहना है कि "यह तकनीक केवल डेटा एकत्र करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नीति-निर्माण में भी एक बड़ा सहायक उपकरण साबित हो सकती है। सरकारें अब यह सटीक रूप से जान सकेंगी कि कौन-से क्षेत्र सबसे अधिक प्रदूषण फैला रहे हैं और किन नीतियों का वास्तविक प्रभाव पड़ रहा है।"

शोध टीम ने नासा के ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी-2 (OCO-2) से कार्बन डाइऑक्साइड और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के सेंटिनल-5पी सैटेलाइट से मीथेन के आंकड़े लिए। इन आंकड़ों से सीधे उत्सर्जन की मात्रा नहीं मिलती, इसलिए विशेष एल्गोरिदम की सहायता से उन्हें विश्लेषित कर उपयोगी रूप में बदला गया। डेटा की सटीकता को परखने के लिए इसे टीसीसीओ (Total Carbon Column Observing Network) नामक अंतरराष्ट्रीय जमीनी नेटवर्क के साथ मिलान किया गया, जिससे इनकी विश्वसनीयता की पुष्टि हुई।

भविष्य की दिशा बताते हुए प्रो. साहू ने कहा, "सैटेलाइट से प्राप्त डेटा अत्यंत उपयोगी है, लेकिन यह बादल, धूल और धुंध जैसी प्राकृतिक बाधाओं से प्रभावित हो सकता है। इसलिए सबसे बेहतर परिणाम सैटेलाइट और ग्राउंड स्टेशन दोनों की निगरानी को मिलाकर ही मिलेंगे। हमारी टीम अब मशीन लर्निंग और भौतिक मॉडलिंग के मिश्रण से इस प्रणाली को और उन्नत बनाने पर काम कर रही है।" आईआईटी बॉम्बे की यह खोज न केवल भारत के लिए, बल्कि वैश्विक जलवायु नीति के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पर्यावरण विशेषज्ञों और सरकारों को अब प्रदूषण के स्रोतों को सटीक रूप से पहचानने, उनके समयानुसार परिवर्तन का मूल्यांकन करने और दीर्घकालिक नियंत्रण रणनीतियां बनाने में अभूतपूर्व मदद मिलेगी।

मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत वर्ली में चला बुलडोज़र, 169 अनधिकृत निर्माण ढहाए गए

मुंबई। शहर में अवैध निर्माणों पर लगातार सख्त रुख अपनाते हुए मुंबई महानगरपालिका ने शुक्रवार को वर्ली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। तटीय सड़क परियोजना के अंतर्गत खान अब्दुल गफ्फार मार्ग स्थित मद्रासवाड़ी इलाके में 169 अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त किया गया। यह अभियान नागरिक मानदंडों के पालन और अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया गया।

मनपा आयुक्त एवं प्रशासक भूषण गगरानी के आदेश पर, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। इस अभियान का नेतृत्व जोन-2 के उपायुक्त प्रशांत सपकाले और दक्षिण जोन की सहायक आयुक्त स्वप्नजा क्षीरसागर ने किया। कार्रवाई में कुल 35 कर्मियों का दल लगाया गया, साथ ही कई मशीनों और उपकरणों की मदद ली गई। नगरपालिका अधिकारियों ने बताया कि इन अनधिकृत निर्माणों के कारण इलाके में जलनिकासी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही थी। मानसून के दौरान बारिश का पानी सड़कों और घरों में भर जाता था, जिससे नागरिकों को भारी असुविधा होती थी। लंबे समय से स्थानीय लोगों की शिकायतों और परियोजना कार्यों में बाधा को देखते हुए यह कार्रवाई आवश्यक मानी गई। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए वर्ली पुलिस स्टेशन की ओर से पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया था। पुलिस कर्मी पूरे समय स्थल पर मौजूद रहे ताकि कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। नगरपालिका ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। अनधिकृत निर्माणों, झोपड़पट्टियों और अतिक्रमणों के विरुद्ध मनपा का अभियान आगामी दिनों में और तेज़ किया जाएगा।

भिवंडी मनपा में भ्रष्टाचार और उत्पीड़न का मामला हुआ उजागर, कर्मचारियों ने की तत्काल कार्रवाई की मांग

भिवंडी: भिवंडी महानगरपालिका के स्वच्छता विभाग में प्रभारी मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक जयवंत मुरलीधर सोनवणे पर भ्रष्टाचार, कर्मचारियों से वसूली, मानसिक उत्पीड़न और पद दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता समीर हनीफ पटेल ने प्रशासन और आयुक्त अनमोल सागर को विस्तृत शिकायत पत्र सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

सूचना के अनुसार, सोनवणे लगभग 1830 सफाई कर्मचारियों की निगरानी करते हैं, लेकिन उनका रवैया अपमानजनक और अत्याचारी बताया गया है। कर्मचारियों ने गालियों, धमकियों और पैसों की वसूली जैसी शिकायतें दर्ज कराई हैं। महिला निरीक्षकों ने भी कार्यस्थल पर असुरक्षा और अभद्र व्यवहार की बात कही।

यह कोई पहला मामला नहीं है। वर्ष 2021 में भी सोनवणे पर लगे गंभीर आरोपों के चलते उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था। नई शिकायत में वित्तीय अनियमितताओं, कार्यालय रिकॉर्ड में गलत विवरण, ठेकेदारों से वसूली, झूठी रिपोर्टिंग और राजनीतिक दबाव का उपयोग करने के आरोप शामिल हैं।

शिकायत में कहा गया है कि सोनवणे कर्मचारियों पर दबाव बनाकर शिकायतें वापस लेने के लिए मजबूर करते हैं। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से आग्रह किया है कि सोनवणे को तत्काल पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ विशेष जांच समिति गठित की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। भिवंडी महानगरपालिका ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

विधायक दिलीप लांडे ने चाँदीवली के नागरिकों को दिवाली उपहार वितरित किए

मुंबई। चाँदीवली विधानसभा क्षेत्र के शिवसेना विधायक दिलीप मामा लांडे ने इस वर्ष भी दिवाली के अवसर पर नागरिकों के बीच निःशुल्क आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। इस सामाजिक पहल के तहत विधानसभा क्षेत्र के 27 हज़ार नागरिकों को सूजी, मैदा, चीनी और अन्य वस्तुएँ भेंट की गईं।

दिवाली उपहार वितरण कार्यक्रम तीन चरणों में आयोजित किया गया। 14 अक्टूबर को वार्ड क्रमांक 157 में चाँदीवली संघर्षनगर स्थित म्युनिसिपल मराठी स्कूल में, 15 अक्टूबर को वार्ड क्रमांक 158 और 159 में साकीनाका पारेरावाड़ी के झुंझार खेल मैदान में, और 16 अक्टूबर को वार्ड क्रमांक 162, 163, 164 और 166 में कुर्ला काजूपाड़ा, छत्रपति शिवाजी मैदान तथा श्री गणेश मंदिर (पंचकुटीर, पवई) के सामने वितरण किया गया।

विधायक दिलीप लांडे ने कहा कि यह उनका कर्तव्य है कि वह अपने क्षेत्र के नागरिकों की दिवाली को मीठा बनाएं। उन्होंने बताया कि शिवसेना के माध्यम से हर साल दिवाली पर सूजी, मैदा और चीनी का वितरण किया जाता है और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जीवनशैली से प्रेरित होकर वह भी नागरिकों की सेवा के लिए दिन-रात तत्पर रहते हैं।

कार्यक्रम में शिवसेना कार्यकर्ताओं और महिला वर्ग का सहयोग सराहनीय रहा, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल और भी मधुर बना।

टाटा नेक्सॉन बनी सितंबर 2025 में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार

मुंबईः टाटा मोटर्स की लोकप्रिय एसयूवी नेक्सॉन ने सितंबर 2025 में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का खिताब हासिल किया। एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट और ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन के साथ नेक्सॉन अब और भी सुरक्षित और स्मार्ट ड्राइविंग अनुभव देती है।

नेक्सॉन भारत की पहली कार है जिसे ग्लोबल और भारतीय NCAP से डुअल 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। कंपनी ने इस सफलता के जश्न में Red #DARK एडिशन लॉन्च किया, जो पेट्रोल, डीज़ल और सीएनजी विकल्पों में उपलब्ध है।

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के CCO विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि नेक्सॉन अपने बोल्ड डिजाइन, बेहतरीन प्रदर्शन और सुरक्षा के साथ भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद बन चुकी है।

गोरेगांव का राजीव गांधी पार्क बना नशेड़ियों का अड्डा, उपेक्षा से बदहाल हुआ नागरिकों का पसंदीदा स्थल

मुंबई। कभी परिवारों, बच्चों और बुजुर्गों से गुलज़ार रहने वाला गोरेगांव (पश्चिम) का राजीव गांधी पार्क आज खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। एमजी रोड के पास मीठा नगर में स्थित यह पार्क स्थानीय लोगों के लिए राहत और मनोरंजन का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब यह नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। मनपा की लापरवाही, रखरखाव की कमी और सुरक्षा के अभाव ने इस पार्क की हालत दयनीय बना दी है।

पार्क की दीवारों पर जगह-जगह गंदगी फैली हुई है, झाड़ियां अनियंत्रित रूप से बढ़ गई हैं और टूटी बेंचों के बीच शराब की बोतलें और नशे के इंजेक्शन बिखरे पड़े हैं। रात ढलते ही यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है। महिलाओं और बच्चों का पार्क में आना-जाना लगभग बंद हो गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी ने इस पार्क को भय का केंद्र बना दिया है।

पार्क में मूलभूत सुविधाओं की हालत बेहद खराब है। शौचालय गंदगी से भरे पड़े हैं और उनमें पानी की सप्लाई नहीं होती। पीने के पानी की व्यवस्था पूरी तरह ठप है। बरसात के दिनों में निकासी प्रणाली बंद पड़ जाने से झूले, स्लाइड और खेल के अन्य उपकरण पानी में डूबकर जंग खा चुके हैं। जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजा करती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा रहता है।

रात के समय सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह नदारद है। आसपास की स्ट्रीट लाइटें महीनों से खराब पड़ी हैं। नशेड़ी और शराबी लोग अंधेरे का फायदा उठाकर खुलेआम नशा करते हैं। पुलिस गश्त के दौरान ये लोग झाड़ियों में छिप जाते हैं और जैसे ही गश्ती वाहन चला जाता है, दोबारा सक्रिय हो जाते हैं। नागरिकों का कहना है कि पुलिस की गश्त केवल दिखावे के लिए होती है और असामाजिक गतिविधियों पर कोई स्थायी नियंत्रण नहीं है।

स्थानीय निवासी तुषार साटम ने बताया कि "शाम के बाद इस पार्क में कदम रखना खतरे से खाली नहीं। महिलाएं और बच्चे अब यहां नहीं आते।

काटेमानेवली के लवकुश टावर में आग, फायर ब्रिगेड की देरी पर भड़के नागरिक, स्थानीयों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

कल्याण। काटेमानेवली स्थित प्रभु राम नगर के लवकुश टावर में गुरुवार देर रात करीब 12 बजे एअर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में धुआं फैलने लगा और इमारत में अफरा-तफरी मच गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग की सूचना फायर ब्रिगेड को तुरंत दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड के लैंडलाइन नंबर पर कॉल न लगने से राहत कार्य में देरी हुई। इसके बाद स्थानीय नागरिकों ने कोळसेवाडी पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मौके पर पहुंचने में करीब 45 मिनट लग गए।

इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता हर्षल सालवी, रणजीत बलवानी, अनिल तिवारी, कुंदन मंडा तिवारी, अम्मू सिंह, विनायक पांडे सहित कई स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। उनकी तत्परता से आग को फैलने से रोक लिया गया, जिससे किसी की जान नहीं गई, हालांकि घर के मालिक भूपेश सिंह को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। स्थानीय नागरिकों ने फायर ब्रिगेड की लापरवाही पर कड़ी नाराज़गी जताई। उनका कहना है कि पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी 'ड' प्रभाग क्षेत्र में ही तैनात थी, लेकिन करीब डेढ़ महीने पहले उसे नेतिवली सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया। लोगों का कहना है कि यदि यह हादसा दिन में होता, तो ट्रैफिक के कारण हालात और गंभीर हो सकते थे।

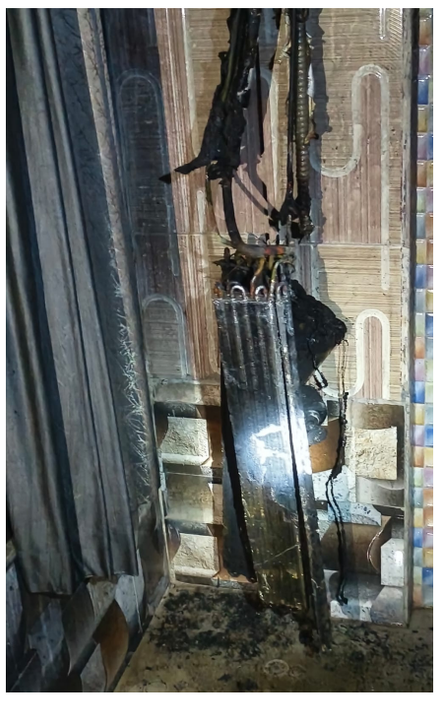

निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पुनः 'ड' प्रभाग क्षेत्र में स्थायी रूप से तैनात की जाए ताकि आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई संभव हो सके। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि फायर ब्रिगेड का आधिकारिक नंबर अक्सर बंद रहता है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

अर्था इंडिया वेंचर्स ने 500 करोड़ रुपये के 'अर्था वेंचर फंड–2' की घोषणा की

मुंबई, 17 अक्टूबर 2025: अर्था इंडिया वेंचर्स (एआईवी) ने अपने दूसरे माइक्रो वीसी फंड, 'अर्था वेंचर फंड–२ (एवीएफ–२)' के लिए २५० करोड़ रुपये के पहले चरण की घोषणा की। फंड का कुल आकार ५०० करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें १०० करोड़ रुपये का ग्रीन-शू विकल्प भी शामिल है। निवेशकों ने पहले ही फंड के ५०% से अधिक निवेश प्रतिबद्धताएँ दी हैं, जिससे अर्था की ठोस रणनीति और ट्रैक रिकॉर्ड का भरोसा स्पष्ट होता है। 'एवीएफ–२' के अंतर्गत प्रारंभिक चरण (सीड स्टेज) में ३६ स्टार्टअप्स में निवेश किया जाएगा, जो प्रीमियम कंजम्पशन, फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, अप्लाइड एआई और डीप टेक जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होंगे। प्रत्येक स्टार्टअप में शुरुआती निवेश लगभग ४ करोड़ रुपये होगा, जिसके बाद फॉलो-ऑन निवेश ८ से १६ करोड़ रुपये तक किया जाएगा। फंड का लक्ष्य प्रमुख स्टार्टअप्स में १५–२०% हिस्सेदारी प्राप्त करना है। फंड की लगभग ८०% पूंजी घरेलू स्रोतों और २०% अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से आएगी। पहले चरण में मिली निवेश प्रतिबद्धताओं का लगभग ९०% हिस्सा भारतीय लिमिटेड पार्टनर्स (एलपी) से और १०% विदेशी निवेशकों से है। फंड के मैनेजिंग पार्टनर अनिरुद्ध ए. दमाणी ने कहा कि यह फंड ऐसे समय में लॉन्च हुआ है जब भारत में प्रारंभिक चरण के निवेश कम हो गए हैं, और इस निवेश से असली, गंभीर और टिकाऊ उद्यमियों को समर्थन मिलेगा, जो ग्राहक राजस्व पर ध्यान केंद्रित करके मजबूत व्यवसाय खड़ा कर रहे हैं।